
इकाई 17 स्वतंत्रतावाद

इकाई की रूपरेखा

- 17.1 प्रस्तावना
- 17.2 स्वतंत्रतावाद क्या है?
- 17.3 स्वतंत्रतावाद की राजनीतिक विचारधारा
 - 17.3.1 व्यक्तिवाद
 - 17.3.2 वैयक्तिक अधिकार तथा स्वतंत्रता
 - 17.3.3 नागरिक समाज
 - 17.3.4 राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरण की समस्या
 - 17.3.5 विधि का शासन तथा सीमित सरकार
- 17.4 आलोचनात्मक मूल्यांकन
- 17.5 सारांश
- 17.6 अभ्यास प्रश्न

17.1 प्रस्तावना

20वीं शताब्दी में उदारवाद कल्याणकारी राज्य के रूप में इस प्रकार उभरा कि उसके कार्यों में कई गुना वृद्धि हो गयी। इस रूपान्तरण के दौरान राज्य ने अपना वर्तमान सर्व-व्यापक रूप धारण किया। परन्तु क्लासिकी उदारवाद ने अपना संघर्ष नहीं त्यागा। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात्, उदारवाद के सिद्धान्त को एक महत्वपूर्ण योगदान उन सिद्धान्तकारों से प्राप्त हुआ, जिनकी नि-ठा प्रारंभिक क्लासिकी उदारवाद की ओर थी। 1960 के दशक के दौरान यह नया आन्दोलन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में लोकप्रिय हुआ और इसे उस समय स्वतंत्रतावाद के नाम से जाना जाने लगा। अनेक स्वतंत्रतावादी रचनाएँ उन लोगों द्वारा लिखी जाने लगी, जो केवल उत्तरी अमेरीकी राजनीतिक संस्कृति और समाज को ही मात्र जानते थे। यह स्वतंत्रतावाद को सार्वजनिकता प्रदान किए जाने का दावा करते हैं, परन्तु, यह क्षेत्रीय अमुक संस्कृति तक ही बनकर रह गया है। 1974 में, हारवर्ड चिन्तक राबर्ट नाज़िक द्वारा रचित रचना, *अनारकी, स्टेट एण्ड यूटोपिया* से स्वतंत्रतावादी आन्दोलन को व्यापक स्तर पर विद्वतापूर्ण आकर्षण प्राप्त हुआ। अपनी सशक्त तर्कबद्धता के कारण इस रचना की खासी प्रशंसा की गयी तथा इसे रॉल्स की रचना *ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस* के बराबर समझा जाने लगा। 1980 के दशक की थैचर/रीगन सरकारों को भी नाज़िक की पुस्तक ने अच्छा प्रभावित किया था। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, स्वतंत्रतावाद का अर्थ है: स्वतंत्र इच्छा अथवा स्वतंत्रता की स्वतंत्र वकालत। यह व्यक्तिवाद का सर्वाधिक आमूल रूप है और इस कारण वैयक्तिकता की निश्चित अभिव्यक्ति तथा उसके पक्ष हेतु स्वच्छ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। राजनीतिक सिद्धान्त में, स्वतंत्रतावाद एक बार फिर आमूल ढंग से इस मूल प्रश्न का उत्तर देता है कि राज्य के वैध कार्य कौन से हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता को पवित्र मानते हुए, स्वतंत्रतावाद यह दावा करता है कि कल्याणकारी राज्य समन्वितवादी राज्य में परिवर्तित हो जाता है। एक प्रश्न उठता है - यदि उदारवादी सिद्धान्तों की जड़ें अमेरिकी तथा अंग्रेज़ी राजनीतिक संस्कृति में विद्यमान हो रही हैं, तो स्वतंत्रतावाद रूपी यह नया

नाम प्रयोग में क्यों लाया गया है? मार्टिन मैसे के अनुसार, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत से उदारवाद का कुछ ऐसा अर्थ बन निकला है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष के तर्क को स्प-टतः प्रतिबंधित नहीं कर पाया है। इस कारण उदारवाद को स्वतंत्रता से जुड़े शब्द की ज़रूरत थी। एक अन्य तर्क यह भी दिया जा रहा है कि ब्रिटेन जैसे देशों में तथाकथित उदारवादी राजनीतिक दल राज्य की शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में समाजवादी राजनीतिक दलों से कुछ थोड़े अधिक संयत हैं, इसलिए शब्द उदारवाद नयी सोच का संकेत नहीं है। स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका एक उदारवादी को प्रायः ऐसा वामपंथी मानता है, जो पूंजी पुनर्वितरणवाद का पक्ष लेता है तथा ऐसी सरकार का समर्थन करता है जो लोगों के जीवन में हर संभव क्षेत्र में हस्तक्षेप करे - एक ऐसी सरकार जो वास्तविक एवं काल्पनिक समस्याओं के समाधान के लिए कर लगाए, खर्चा करे तथा हर काम के लिए लोक सेवा (अर्थात् अफसरशाही द्वारा) कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करे। सारांश यह कि आज का उदारवाद ऐसे अत्याचारी राज्य की स्थापना का प्रयास कर रहा है, जो अप्राप्तिय सम-टिवादी यूटोपिया के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करने में तनिक भी संकोच नहीं करता। अतः ऐसा सोचा जाने लगा कि इस प्रकार के उदारवाद का क्लासिकी उदारवाद से दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं है। फलस्वरूप नयी खोज के अनुरूप शब्द 'स्वतंत्रतावाद' का प्रयोग अधिक सार्थक दिखायी देने लगा। स्वतंत्रतावाद उदारवादी विकास के प्रारंभिक कालों से प्रेरित हुआ है। लगभग एक शताब्दी बाद, जिसके दौरान सम-टिवादी तथा सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा, यह महसूस किया गया कि राज्यवाद की बढ़ती लहर का मुकाबला करने के लिए क्लासिकी उदारवाद न तो सशक्त था और न ही सैद्धान्तिक। स्वतंत्रतावादी विचारक वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा बाज़ार अर्थव्यवस्था और राज्य शक्ति के विरोध में पारंपरिक उदारवादियों की अपेक्षा अधिक सुसंगत और अधिक आमूल हैं। स्वतंत्रतावादी विद्वानों ने स्प-ट किया है कि यह व्यक्तियों की विकेंद्रित कृति है, जो स्वतंत्र बाज़ार में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं और जिस कारण एक स्वचालित व्यवस्था बनती भी है और बनी भी रहती है। ऐसी व्यवस्था में पर्याप्तता तथा सम्पन्नता संभव हो सकती है और ऐसी व्यवस्था में ही एक जटिल सभ्यता जिसमें हम रहते हैं, को समर्थन मिलता है।

17.2 स्वतंत्रतावाद क्या है?

गत तीन शताब्दियों में राजनीतिक व नैतिक दर्शन का सम्बन्ध अधिकांशतः मानव स्वतंत्रता से रहा है। राजनीति के उस वैचारिक दृ-टिकोण को जिसे स्वतंत्रतावाद कहते हैं, वह स्वतंत्रता के विचार को ऐसे दूरतम छोर तक ले जाता है, जहाँ स्वतंत्रता राज्य के लिए उसके नागरिकों के संदर्भ में एक मात्र अभिरुचि का तत्व रहा जाता है।

स्वतंत्रतावादी दर्शन अनेक विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनमें एफ. ए. हेयक, कार्ल पॉपर, तालमन, मिल्टन फ्रीडमन, आई. बर्लिन, एम. रॉथबार्ड, रॉबर्ट नाज़िक, अइन रैण्ड आदि उल्लेखनीय नाम हैं। स्वतंत्रता को अंततः आदर्श मानते हुए, स्वतंत्रतावाद मानता है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, एक समाज में सशक्त निजी सम्पत्ति अधिकार होने चाहिए; एक स्वतंत्र बाज़ार होना चाहिए तथा एक न्यूनतम सरकार होनी चाहिए। कुछ लेखकों ने स्वतंत्रतावाद को 'स्वतंत्रता' कहा है। इन विभिन्न अवधारणाओं को समझने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि हम यह जान लें कि स्वतंत्रतावाद का किसमें विश्वास है। कुछ शब्दों में, स्वतंत्रतावाद का यह मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता वह मूल मूल्य है, जो सभी सामाजिक सम्बन्धों, आर्थिक आदान-प्रदानों तथा राजनीतिक व्यवस्था के मूल में रहती है। स्वतंत्रतावादी अनिवार्यता: यह प्रचार करते हैं कि स्वतंत्रता हर क्षेत्र में होनी चाहिए। व्यक्ति

जो चाहे वह कर सकता है, बशर्ते वह दूसरों की सम्पत्ति तथा स्वतंत्रता को कोई हानि न पहुँचाएँ। स्वतंत्रतावादियों का मत है कि राज्य द्वारा दमन-दबाव की अपेक्षा, स्वतंत्र बाज़ार व्यवस्था में, लोगों द्वारा ऐच्छिक सहयोग सदैव बेहतर होता है। उनका विश्वास है कि समाज के नाम पर राज्य की भूमिका लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं है। राज्य इसलिए नहीं होता कि वह धन का पुनर्वितरण करे, संस्कृति को प्रोत्साहित करे, कृषि क्षेत्र को सहारा दे, छोटी-छोटी कम्पनियों को सहायता दे। उसका काम व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना है तथा यह देखना है कि नागरिक शान्तिपूर्वक तरीकों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रयासरत रहें। स्वतंत्रतावाद कानून के समक्ष प्रत्येक तथा सबकी औपचारिक समानता का समर्थन करता है। उसे अमीर तथा गरीब के बीच असमानताओं की अधिक चिन्ता नहीं है - ऐसी असमानताएँ अनिवार्य हैं, इन्हें निजी स्वतंत्रता को कम करने अथवा सम्पन्नता को कम करके ही कम किया जा सकता है। स्वतंत्रता से संघर्ष करने का सर्वोत्तम तरीका स्वतंत्र उद्यम तथा स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था का आश्वासन है; दान सम्बन्धी पहल जैसे तरीके जो अपेक्षाकृत अधिक कारगर हैं तथा नैतिक दृष्टि से उचित भी हैं, ज़रूरतमंदों का बचाव कर सकते हैं। स्वतंत्रतावादियों का मत है कि निजी स्वतंत्रता को बनाए रखने का तरीका यह है कि निजी सम्पत्ति की अनुल्लंघनीयता की गारण्टी दी जाए, सरकार के आकार को जहाँ तक संभव हो, सीमित किया जाए तथा उसके हस्तक्षेपों की सीमा को कम किया जाए। वह समझते हैं कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने में असमर्थ होता है।

स्वतंत्रतावाद सभी प्रकार की सम-टिवादी विचारधाराओं का विरोध करता है, भले वह विचारधाराएँ वामपंथी राय की हों अथवा दक्षिणपंथी की। यह विचारधाराएँ समूह, रा-द्र, सामाजिक वर्ग, भले वह लिंग पर आधारित हो अथवा जाति पर, धार्मिक हों अथवा भा-ायी हों, आदि की प्राथमिकता पर बल देती हैं। वह उन सबका विरोध करते हैं, जिनका उद्देश्य सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में, व्यक्तियों को अनुशासित करना हो। वह ऐसे सामूहिक रूप के समूहों की प्रासंगिकता को नकारते तो नहीं हैं, परन्तु वह कहते हैं कि यह व्यक्तियों पर ही छोड़ दिया जाए कि वे किस/किन समूहों में प्रवेश करना चाहेंगे तथा कितना योगदान देंगे। यह राज्य अथवा संस्थाओं का काम नहीं है कि वह दफतरशाही तथा उत्पीड़न तरीकों से अपने लक्ष्यों को लोगों पर थोपने का प्रयास करें।

स्वतंत्रतावाद 20वीं शताब्दी की मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमों को अस्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रतावाद राज्य के बढ़ते विकास हेतु उसके आकार का खण्डन करता है; वह नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में सभी प्रकार के हस्तक्षेपों को मानने से इन्कार करता है। केवल यह आमूल परिवर्तनों की माँग करता है तथा उन परिवर्तनों के लिए कार्यरत रहता है - यह राज्य के आकार तथा उसकी भूमिका में व्यापक कमी चाहता है; यह केवल स्वतंत्रतावादी ही हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को अन्य सभी की अपेक्षा महत्व देते हैं। अधिक से अधिक लोगों ने यह महसूस करना आरंभ कर दिया है कि स्वतंत्रतावाद ही मात्र एक विकल्प रह गया है। 1960 के दशक में अमेरिका में शायद ही कोई स्वतंत्रतावाद प्रकार का आन्दोलन था, परन्तु 1970 के दशक में इस आन्दोलन ने खासी उड़ान ली है। शैक्षिक जीवन में सम-टिवादी धारणाओं तथा कीन्सीय अर्थशास्त्र का प्रभुत्व बना रहा, परन्तु हाल के कुछ वर्षों में समस्त संसार में क्लासिकी उदारवाद तथा बाज़ारू अर्थव्यवस्था में रुचि जागृत हुई है। लगभग एक शताब्दी के तिरोभाव के पश्चात् क्लासिकी उदारवाद अपने शिशु स्वतंत्रतावाद सहित एक प्रभावकारी दार्शनिक सिद्धान्त के रूप में तथा 21वीं शताब्दी में एक आन्दोलन के रूप में उभर रहा है।

सभी दार्शनिक कल्याणकारी राज्यों की भांति, स्वतंत्रतावाद के भी विविध रूप हैं: अनेक प्रकार के दृष्टिकोण तथा उप-समूह जिसके कारण उसके सैद्धान्तिक औचित्यों में कोई सर्वसम्मति दिखाई नहीं

देती और न ही उनके लक्ष्यों व रणनीति को जो वह अपनाते हैं, उनमें कोई एकरूपता दिखायी देती है। मुख्यतः स्वतंत्रतावाद के दो रूप हैं और प्रत्येक दृष्टिकोण सम्बद्ध संदेहों का उत्तर देता है। एक दृष्टिकोण, अराजकतावादी अथवा अराजक-पूँजीवादी कहे जा सकते हैं, वे राज्य का पूर्णतः अभाव चाहते हैं तथा राज्य से जुड़े सभी कार्यों का निजीकरण। यह दृष्टिकोण, पहली नज़र में दूरस्त छोर का तथा बेतुका दिखायी पड़ता है, परन्तु वस्तुतः यह स्वयं किसी सैद्धान्तिक युक्तिसंगत तर्क पर आधारित है। उदाहरणतः ऐसी कल्पना की जा सकती है कि प्रान्तीय सरकार अथवा नगरपालिकीय पुलिस बलों (जो भ्र-टाचार, शक्तियों के दुरुपयोग, अयोग्यता, पक्षपात से ग्रस्त होते हैं तथा स्वयं दण्ड से मुक्त रहते हैं) के स्थान पर निजी सुरक्षा अभिकरणों की व्यवस्था की जाए। ऐसे अभिकरण नागरिकों की रक्षा करके तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करके लाभ अवश्य बनाएँगे। अराजक-पूँजीपति, सेना तथा न्यायालयों के निजीकरण से सम्बन्धित लगभग वह तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिनसे राज्य के लिए कोई कुछ न करने के लिए छोड़ा जाता है। ऐसी व्यवस्था में निजी कम्पनियाँ व्यक्तियों को वह सभी सेवाएँ उपलब्ध कराएँगी जो उन्हें एक स्वतंत्र बाज़ार में चाहिए होंगी। उस परिप्रेक्ष्य में जब जन-व्यय ज़रूरत से भी दुगुना होता है और सरकार कानून पर कानून बनाते नहीं थकती और लोगों पर राज्य का नियंत्रण सदैव बढ़ता रहता है, स्वतंत्रतावादी तर्क ऐसी प्रवृत्ति को उलट करके अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी दिखायी देता है, क्योंकि इसके अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा तथा राज्य के अत्याचार में कमी की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। स्वतंत्रतावाद का दूसरा रूप लघुराजवादी (miniarchism) है। लघुवादियों का मत है कि राज्य को पुलिस सुरक्षा, अनुबंधों को कार्यरूप दिलाना, रा-द्रीय सुरक्षा, विदेशी सम्बन्ध, न्याय, लोगों के अधिकारों तथा निजी सम्पत्ति की रक्षा जैसे कार्य करने चाहिए। शेष सभी कार्यों का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि एक अति विकेन्द्रकृत संघीय राज्य में स्थानीय सरकारें अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकती हैं तथा नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाओं का प्रबंध कर सकती हैं, ताकि असंतु-ट नागरिक निराश न हों। उनके अनुसार, राज्य को निश्चितः कर लगाने का अधिकार नहीं होगा और उपर्युक्त कार्यों के लिए पूँजी प्राप्त करने की भी शक्ति नहीं होगी। प्रश्न यह उठता है कि स्वतंत्रतावादियों के विचारों, राजनीतिक सिद्धान्त को लेकर इतनी भिन्नताएँ क्यों हैं? इसका पहला मुख्य कारण यह है कि स्वतंत्रतावादी व्यक्तियों के सम्पत्ति प्राप्ति तथा उसे बनाए रखने के अधिकार को विशेष रूप से तथा व्यक्तियों के अधिकारों को सामान्यतः अति महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका विश्वास है कि सम्पत्ति का अधिकार तथा अनुबंध स्वतंत्रता का अधिकार कल्याणकारी अधिकारों से मेल नहीं खाता, क्योंकि ऐसे अधिकारों के वास्तविक प्रयोग में किसी दूसरे के श्रम का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। स्वतंत्रतावादियों के विचारों में भिन्नता का दूसरा कारण यह है कि स्वतंत्रतावादी मानते हैं कि अहस्तक्षेत्री पूँजीवाद की अप्रतिबंधित व्यवस्था ही एक सर्वोत्तम वांछनीय सामाजिक व्यवस्था है। राज्य बन्धनों से मुक्त लोग अहस्तक्षेत्री पूँजीवादी व्यवस्था को स्वभावतः स्थापित करेंगे और फिर ऐसी व्यवस्था की स्थापना सबके लिए सर्वश्रे-ठ है। इन सभी पहलुओं का अध्ययन रुचिकर होगा।

17.3 स्वतंत्रतावाद की राजनीतिक विचारधारा

ऐसा दावा किया जाता है कि स्वतंत्रतावाद की विचारधारा की महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ अनेक शताब्दियों के फलस्वरूप विकसित हुई हैं। प्राचीन चीन, यूनान तथा आधुनिक इज़रायल में इससे सम्बंधित कुछेक संकेत मिलते हैं। आधुनिक स्वतंत्रतावादी चिन्तन में ऐसी संकल्पनाओं का थोड़ा-बहुत विवरण जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, थॉमस जैफरसन, थॉमस पेन जैसे 17वीं 18वीं शताब्दियों के

विचारकों की रचनाओं में मिलता है। 20वीं शताब्दी में इन संकल्पनाओं को पुनः खोज करने में नव-उदारवादी विचारकों जैसे माइकल ऑकशाट, एफ. ए. हेयक, मिल्टन प्रीडमन, रॉबर्ट नाज़िक की भूमिका रही है। जहाँ इन विद्वानों ने स्वतंत्रतावादी आन्दोलन को नया बौद्धिक जीवन प्रदान किया है वहाँ निजी स्वायत्तता के विचार ने इसे वैयक्तिक आधार प्रदान करने हेतु बीज अर्पित किए हैं। स्वतंत्रतावादी सिद्धान्त की कुछेक अनिवार्य संकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं।

17.3.1 व्यक्तिवाद

यह सही है कि स्वतंत्रतावादी आदर्श में व्यक्तिवाद की संकल्पना का पारिवारिक सम्बन्ध नव-क्लासिकी पूंजीवाद, अराजक-व्यक्तिवाद तथा क्लासिकी उदारवाद आदि से रहा है, परन्तु ऐसा सोचना कि व्यक्तिवाद की संकल्पना इन सबसे बनी है, सही नहीं होगा। स्वतंत्रतावाद को सर्वसत्तावाद के उदय तथा 1930 के दशकों के आधुनिक कल्याणकारी राज्य के पृ-ठपट में ही समझा जा सकता है। स्वतंत्रतावादी व्यक्ति को सामाजिक विश्लेषण की मौलिक इकाई मानते हैं, व्यक्ति ही प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करते हैं तथा वे ही अपनी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी समझे जाते हैं। स्वतंत्रतावादी चिन्तन व्यक्ति की प्रति-ठा पर बल देता है जिसका अर्थ है, व्यक्ति के अधिकार तथा उनका दायित्व, अधिक लोगों के लिए प्रति-ठा का प्रगतिशील विस्तार - अधिक महिलाओं, विभिन्न धर्मों के अधिक लोगों, विभिन्न जातियों के अधिक लोगों के लिए। व्यक्ति की प्रति-ठा, उसका मान-सम्मान, पश्चिमी समाज में व्यक्ति की प्रति-ठा, उसका मान-समान एक महज स्वतंत्रतावादी उपलब्धि हैं।

अराजकतावाद तो नहीं, स्वतंत्रतावादी व्यक्तिवाद का अतिमूल रूप है। व्यक्तिवाद के साथ, स्वतंत्रतावादी वैयक्तिकता की सबलता तथा पूंजीवादी वैयक्तिकता की स्प-ट अभिव्यक्ति का गुणगान करता है। स्वतंत्रतावादी के कुछेक अराजकतावादी तत्व उसके लिए 'अराजक-पूंजीवाद' की संज्ञा अवश्य देते हैं। यह और बात है कि पूंजीवाद के प्रति स्वतंत्रतावादी का विश्वास जिस प्रकार की असमानता को वह वैध बना देता है, अराजकतावादी उस प्रकार की असमानता को स्वीकार नहीं करते। अईन रैण्ड की रचनाएँ व्यक्तिवाद के स्वतंत्रतावादी आदर्श की अभिव्यक्ति करती हैं, यद्यपि इन रचनाओं का रूप कहीं कहीं दूरस्त छोर तक पहुँच जाता है और कहीं कहीं वह प्रभावित भी नहीं करता। एक अच्छे उपन्यासकार की भांति अपने अपने उपन्यास-रचनाओं तथा खण्डनात्मक सम्बन्धों में स्वतंत्रतावादी आदर्श को विकसित करने का प्रयास करते हैं। उन सभी विचारों अथवा धर्म-वैज्ञानिक अवधारणाओं को अस्वीकार करते हुए जो व्यक्ति को समाज के अधीन बताते हैं, यह मत व्यक्त किया कि व्यक्ति समाज की मूल इकाई है, नैतिक महत्त्व का मुख्य बिन्दु है तथा मानवीय सृजन का एक मात्र स्रोत है। उसके अनुसार, हमारी आधुनिक परेशानियों का मूल कारण परहितवाद का दर्शन है - एक ऐसी नैतिक स्थिति जो वैयक्तिकता के सर्वोच्च मूल्य का प्रभावपूर्ण ढंग से सर्वनाश करती है। परहितवाद, न कि धन, की अवधारणा जो अपने से ऊपर दूसरों के कल्याण को बड़ा मानती है, सभी त्रुटियों की जड़ है। वास्तव में, धन तो व्यक्ति की अन्तर्निहित उत्कृ-टता उचित का अनुमान तथा उसके परिश्रम का फल है। रैण्ड के लिए परहितवाद एक दुर्गुण तथा स्वार्थता एक सदगुण है: स्वार्थता का अर्थ छोटी-छोटी चिकनी-चुपड़ी भोगासक्ति नहीं है, अपितु अपने जीवन तथा भाग्य के प्रति अपनी सम्पूर्ण जिम्मेदारी है। परहितवाद सम्पूर्ण परेशानी है क्योंकि यह आदाता के रोगग्रस्त अपराधक भावनाओं को आवश्यकता से अधिक महत्त्व देता है तथा प्राप्त करने वाले को निरंतर चापलूसी की स्थिति में रखता है, दोनों में जीवन के प्रति विश्वस्त दृ-टिकोण जागृत नहीं होता, जिसका अंत वस्तुओं व सेवाओं में उचित तथा समानांतर आदान-प्रदान में सम्पन्न होना चाहिए। परहितवाद का आचरण आनुग्रहिक होता है। यह इस तथ्य का प्रचार है कि किसी को किसी पर सवारी करने का आदेशात्मक अधिकार है। इस के अनुसार, यह

विचार कि कोई दूसरे के लिए अपने आपका त्याग करने को तत्पर है, अपने आपमें आमूलतः एक त्रुटि है। यह मानव प्रति-ठा का अपमान है। यह मृत्यु को जीवन पर प्राथमिकता देने का निमन्त्रण है।

17.3.2 वैयक्तिक अधिकार तथा स्वतंत्रता

स्वतंत्रतावाद के मूल में यह एक तथ्य निहित है कि व्यक्ति को दूसरों के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। निजी स्वतंत्रता एक सर्वोच्च नैतिक गुण है। अतः एक व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित तब होती है जब वह बन्धनों की सहमति देता है। कोई भी बंधन, पुनर्वितरण हेतु आय पर कर लगाना सहित, उचित नहीं है। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रतावाद अपने सिद्धान्त को अधिकारों की भा-ना में व्यक्त करती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्राकृतिक नकारात्मक अधिकार होते हैं। कम से कम जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के अधिकार। कोई भी उसे हानि नहीं पहुँचा सकता, कोई भी उसकी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकता, कोई भी उसकी सम्पत्ति नहीं ले सकता, उसकी सहमति के बिना कोई उसके अधिकारों की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, कुछ सामान्य रूप के भी अधिकार होते हैं, जो पूरी दुनिया के विरुद्ध लागू होते हैं। क्योंकि ऐसे अधिकारों को कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए पूरे संसार के लोगों का यह कर्तव्य है कि वह अधिकार-प्राप्त लोगों के जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति में हस्तक्षेप न करें। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने मनु-य होने के नाते यह अधिकार है कि उसे अपनी नैतिक रक्षा के लिए कुछ करना नहीं होता। एक व्यक्ति के पास उसके अधिकारों के होने हेतु दूसरों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। यह अधिकार उसके व्यक्ति होने का अनिवार्य संघटक हैं। यह सरकार अथवा समाज द्वारा प्राप्त नहीं होते; यह व्यक्तियों के स्वरूप में निहित होते हैं। यह सहज रूप से सही है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का आनन्द लेते हैं, दूसरों द्वारा इन अधिकारों को छीनना उनके लिए जवाबदेही का बोझ बन सकता है। प्रायः स्वतंत्रतावादी सिद्धान्तकार नकारात्मक अधिकारों तथा स्वतंत्रता के आगे-पीछे के बीच से जुड़ी बातें करते हैं कि अधिकारों का कोई भी सिद्धान्त निजी स्वतंत्रता की जड़ में होता है। ऐसी कभी भी कोई स्थिति नहीं होती, जबकि नकारात्मक सामान्य अधिकारों की व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी स्वतंत्रता को सीमित करते हुए अवहेलना हो। उदाहरणतः 'क' के सम्पत्ति (अथवा जीवन या स्वतंत्रता) के अधिकार को दूसरों के लाभ (उनके सकारात्मक अधिकारों की संतुष्टि आदि) की अवहेलना नहीं की जा सकती। 'क' स्वयं अपनी सम्पत्ति को किसी को दान रूप में छोड़ सकता है, अथवा अपनी इच्छानुसार किसी को अपनी सम्पत्ति पर सकारात्मक रूप से अधिकार रखने की आज्ञा दे सकता है। किसी को भी नैतिक रूप से विवश नहीं किया जा सकता कि वह कानूनी अथवा नैतिक नियमानुसार अपने जीवन, स्वतंत्रता व सम्पत्ति को छोड़ दे। यह नैतिक/कानूनी नियम इस बात की गारण्टी है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता (जीवन, सम्पत्ति, आदि) उस की सहमति के बिना सीमित नहीं की जा सकती।

अधिकारों के संदर्भ में जो तथ्य नोट करने योग्य हैं, वह यह हैं कि स्वतंत्रतावादी नकारात्मक तथा सकारात्मक अधिकारों में भेद करते हैं। उदाहरणतः जीवन के अधिकार को ही लीजिए: इसके नकारात्मक अर्थ में इस अधिकार के वि-य में यह कहा जाएगा कि जीवन रखने वालों को किसी दूसरे द्वारा मारा नहीं जाएगा; सकारात्मक अर्थ में, इस अधिकार के वि-य में यह कहा जाएगा कि दूसरों को जीवन रखने वाले के जीवन को बचाने में सहायता की जाए, यदि दूसरों के लिए ऐसी सहायता संभव हों। इस भेद का महत्व यह है कि स्वतंत्रतावादी यह मत व्यक्त करते हैं कि लोगों के पास मूल सकारात्मक अधिकार नहीं हैं; उनके पास तो सकारात्मक दायित्व हैं, जिन्हें वे दूसरों के प्रति निभाने के लिए उन्हें अपने दायित्वों का आश्वासन देना चाहिए कि वह अपने संकेतात्मक कार्यों को निभाने का वचन देते हैं।

अतः स्वतंत्रतावाद के दो सुप्रसिद्ध विशेषताएँ देखी जा सकती हैं: **पहली**, नकारात्मक सामान्य अधिकारों का प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है; यह आश्वासन देना है कि बिना सहमति किसी के जीवन को नियन्त्रित नहीं किया जाएगा। या जैसा कि नॉज़िक ने कहा है, कृति पर सम्बद्ध बन्धन (जो नकारात्मक सामान्य अधिकार माने जा सकते हैं) कान्ट के मूल सिद्धान्त को दर्शाते हैं जिसमें वह कहता है कि व्यक्ति साध्य होते हैं, मात्र साधन नहीं, उन्हें बलि नहीं चढ़ाया जा सकता अथवा किन्हीं दूसरों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें प्रयोग भी नहीं किया जा सकता (यह बन्धन इस सत्य को भी दर्शाते हैं कि हमारा अस्तित्व दूसरों से अलग है)। यह बन्धन इस सत्य को भी दर्शाते हैं, कि हमारे बीच को अन्य संतुलित करने की कृति नहीं घट सकती।” **दूसरा**, स्वतंत्रतावादियों का मत है कि किसी नैतिक नियम के खण्डन करने का कारण यह है कि ऐसा नियम किसी की, उसकी सहमति के बिना, स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। हेयक, उदाहरणतः तर्क देते हैं कि हमें सरकार के विस्तार की सभी योजनाओं की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे विस्तार से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। रॉल्स के विरुद्ध नॉज़िक की मुख्य शिकायत यह है कि रॉल्स के दोनों सिद्धान्त व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि स्वतंत्रतावाद स्वतंत्रता से जुड़ी विचारधारा है। स्वतंत्रतावाद स्वतंत्रता का एक मात्र मानक मानने के विरुद्ध इसे व्यक्ति का एक मात्र अधिकार समझता है। इसे ‘असत्तामूलक स्वतंत्रतावाद’ भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के एक सामान्य अधिकार का भाव यह निकलता है कि हम सरकार से यह अपेक्षा करें कि वह व्यक्तियों को कुछ करने के लिए विवश न करे। इससे यह विचार स्पष्ट होता है कि हमारा केवल एक ही मौलिक अधिकार है और वह है स्वतंत्रता का अधिकार; शेष सभी अधिकार इस अधिकार के अधीन हैं - वह सभी अधिकार या तो विशेष रूप के हैं या स्वतंत्रता के अधिकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए गए हैं।

नकारात्मक अधिकारों की संकल्पना की भांति, स्वतंत्रतावाद स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू पर जोर देता है: स्वतंत्रता को दूसरों के अधिरोपण के अभाव के रूप में विशेषतः उन अधिरोपणों से, जो उनके जान-बूझ की गतिविधियों के कारण पनपते हैं। इस रूप में, प्रत्येक व्यक्ति वह कुछ करने का हक रखता है, जो वह करना चाहता है अथवा वह जिसे वह ठीक समझता है, उन्हें छोड़कर जब उसकी गतिविधियाँ दूसरों पर कुछ थोपी जाती हैं, अथवा दूसरों की गतिविधियों दूसरों, पर कुछ थोपी है अथवा दूसरों की गतिविधियों में हस्तक्षेप करती हैं। ऐसा जिसे हॉब्स ने ‘बाहरी बाधाओं का अथवा दूसरों के साथ शान्ति प्राप्ति की इच्छा’ या ‘युद्ध न करना’ कहा था, या जिसे लॉक के शब्दों में ‘जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता अथवा सम्पत्ति को क्षति न पहुँचाना’ कहा गया अथवा काण्ट के अनुसार ‘उन सिद्धान्तों पर कार्य करने जो प्रत्येक व दूसरों की स्वतंत्रता की इच्छा के साथ रह सके।” समसामयिक अमेरिकी विचारक जॉन रॉल्स के स्वतंत्रता के प्राथमिकता के सिद्धान्त में भी ऐसा ही कुछ विवरण मिलता है: “प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता की व्यापक व्यवस्था की प्राप्ति का समान अधिकार प्राप्त है, जोकि सभी को समान रूप से मिले।” इन सभी कथनों में जो महत्व का तथ्य है, वह नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देना है; एक दूसरे की मुठभेड़ में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जो दूसरों को हानि पहुँचाएँ तथा उनके लिए खतरा, विकार आदि पैदा करे; वह सभी गतिविधियाँ की जा सकती हैं, जिनका प्रभाव किसी की वृद्धि हो। स्वतंत्रतावादी अवपीड़न को स्वतंत्रता का अवरोधक मानते हैं। उनके अनुसार, स्वतंत्रतावाता, अवपीड़न का अभाव है, वह इसे प्रकट बल समझ उसका खण्डन करते हैं। स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव है, यह थोपी गयी लागत है; उत्पीड़न करने वाला पीड़ित पर लागत थोपता है।

प्राकृतिक आधारित जिसकी स्वतंत्रतावादी अपील करते हैं, वह हमारा शरीर है। स्वतंत्रतावादियों का कहना है कि हमें प्रत्येक की स्वतंत्रता को अधिकार में बदलना है। दूसरे शब्दों में, किसी की स्वतंत्रता के विरुद्ध किन्हीं/किसी के अधिरोपण को उसके विरुद्ध कार्यवाही अथवा उसे अपनी सीमा में रहने के लिए की गयी कार्यवाही का कारण बनाया जाना चाहिए - स्वतंत्रतावादी इसी प्रकार की कार्यवाही को करने की बात करते हैं। इस प्रकार के अधिकार को स्व-स्वामित्व का अधिकार के समान समझा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए अपना स्वामी है, ठीक उसी प्रकार जैसे हम अनेक प्रकार की वस्तुओं जैसे 'कारों', तथा 'फुटबालों' के स्वामी हैं। उसी रूप में जैसे हम अपने लिए कुछ करते हैं, उसकी प्रकार हम दूसरों के लिए तथा दूसरों के साथ नहीं करते, अथवा दूसरों के साथ कुछ करने के लिए हमें उनकी सहमति/आज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। हम दूसरों की इच्छाओं के विरुद्ध उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते।

अंततः यह पूछा जा सकता है कि लोग स्वतंत्रता को महत्व क्यों देते हैं? स्वतंत्रतावादियों के लिए स्वतंत्रता कोई वस्तु नहीं है, जैसे कार या मूंगफली रूपी मक्खन, यह तो गतिविधि/कृति करने की आवश्यक स्थिति होती है। उस रूप में जैसे यदि हम कोई अमुक कार्य करते हैं, तो यह ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कोई हमें वैसा करने से न रोक सके। स्वतंत्रता उस स्थिति का नाम है, जो हमें जो कुछ है उसे करने के योग्य बनाती है: उसे करने की स्वतंत्रता जिसे किया जाना हो। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता कुछ ऐसी-वैसी स्थिति नहीं है, जो हवा में हो कि यह अच्छी है या नहीं है। स्वतंत्रता कोई मूल्य/मानक भी नहीं है, यह कृति/गतिविधि की अवस्था अर्थात् शर्त है, कुछ करना अथवा कुछ करने की प्रेरक।

17.3.3 नागरिक समाज

लोगों को जीवित रहने तथा विकसित करने के लिए समाज में व्यवस्था का होना ज़रूरी है। ऐस सोचना आसान होता है कि किसी केन्द्रीय सत्ता द्वारा व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, वैसे जैसे हम कर एकत्रित करने के लिए व्यवस्था लागू करते हैं या फुटबाल टीम में अनुशासन स्थापित करते हैं। स्व-समतावादी सामाजिक विश्लेषण की अंतर्दृष्टि यह है कि समाज में व्यवस्था अनायास हज़ारों तथा करोड़ों लोगों में अपने आप आ जाती है जब वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने कार्यों में समन्वय करते हैं। हमने अपने लिए स्वतंत्रता की कामना की है, परन्तु साथ में एक पेचीदा संगठन सहित एक जटिल समाज बनाने का संकल्प भी किया है। मानव समाज में कानून, भा-गा, पूँजी, बाज़ार आदि यह सब बिना किसी केन्द्रीय निर्देशन के अपने आप विकसित होते हैं। नागरिक समाज सादृष्टिक व्यवस्था का एक उदाहरण है; उसमें बने संघ-समुदायों का अपना-अपना उद्देश्य होता है, परन्तु नागरिक समाज कोई संगठन नहीं होता तथा उसका अपना कोई विशेष उद्देश्य भी नहीं होता। जिनके साथ मिलकर हम इन संघ-समुदायों को बनाते हैं, उन सब से मिलकर नागरिक समाज बनाता है। इन संघ-समुदायों के विभिन्न रूप जैसे परिवार, चर्च, स्कूल, क्लब, बन्धुत्वकारी सोसाइटियाँ, सहशासित समुदाय, अड़ोस-पड़ोस तथा वाणिज्य से जुड़े रूप जैसे साझेदारी, निगम, श्रम यूनियन, व्यापार समुदाय होते हैं। यह सब संघ समुदाय विभिन्न तरीकों से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। नागरिक समाज को समाज के एक स्वाभाविक एवं ऐच्छिक समुदायों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कुछ विश्लेषणकर्ता व्यापारिक तथा गैर-लाभकार संगठनों में भेद करते हैं तथा यह तर्क देते हैं कि व्यापार बाज़ार का एक अंश है, नागरिक समाज का नहीं। परन्तु, बाँज़ के अनुसार, भेद उन संघ-समुदायों में होना चाहिए जो अवपीड़न करते हैं जैसे राज्य तथा उन में जो स्वाभाविक व ऐच्छिक होते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि बनाया गया समुदाय लाभ बना रहा हो या कोई उद्देश्य पूरा कर रहा हो,

ज़रूरी यह है कि समुदाय में हमारी भागीदारी स्वैच्छिक हो। इस तथ्य को नोट करना आवश्यक है कि नागरिक समाज के भिन्न अंग होते हैं, परन्तु नागरिक समाज का स्वयं का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। यह तो अधोहस्ताक्षरी है, सभी उद्देश्यरत समुदायों का अपने-आप उभरता-निखरता प्रतिफल/परिणाम। संघ-समुदाय लोगों को लोगों के साथ जोड़ते हैं। इनमें से कोई भी राज्य किसी एक के व्यक्तित्व को न तो खाली करता है, और न ही पूर्ण रूप से परिभाषित। स्वतंत्रतावाद की इस अवधारणा में, हम विभिन्न तरीकों से विभिन्न लोगों को स्वतंत्र तथा ऐच्छिक सहमति के आधार पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। अरनैस्ट गैलनर कहते हैं कि आधुनिक नागरिक समाज को 'मापांक व्यक्ति' की आवश्यकता है। उस व्यक्ति से विपरीत जो किसी विशेष-संस्कृति से बनता है तथा उसमें समा जाता है, मापांक व्यक्ति 'अपने आपको बिना बाँधे विशेष-उद्देश्यों के तदर्थ तथा सीमित समुदायों में जोड़ सकता है'। वह दूसरों के साथ सम्पर्क बना सकता है जो 'भले लचीले, विशिष्ट, साधक परन्तु प्रभावपूर्ण हों और जो व्यक्तियों के रूप में, विभिन्न तरीकों में, समाज के बनाए जाने में सहायक हों' - ऐसा समाज नहीं जो बन्द प्रकार का हो अथवा ऐसा समाज भी नहीं, जैसे मार्क्सवादी मसीहा जैसा बनने का वचन देते हैं अथवा रा-ट्रीय समाजवादी (अर्थात् हिटलर के समय का नाज़ी समाज) अथवा सर्व धर्मों का समाज भी नहीं, अपितु ऐसा समाज जो ऐच्छिक समुदायों के दायरे में स्वतंत्र व्यक्तियों का समाज होता है। व्यक्ति ऐसे समाज से प्रकट नहीं होते, समाज ऐसे व्यक्तियों से प्रकट होता है। ऐसा समाज ऐसे प्रकट नहीं होता, मानो किसी ने उसकी निर्माण-योजना बनाई हो, और न ही राज्य ऐसे समाज की स्थापना करता है। यह समाज तो अपने आप बन जाता है, अपनी ज़रूरतों तथा इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग दूसरों के साथ आ मिलते हैं। राज्य कानूनी नियमों द्वारा शासित व्यक्तियों का समुदाय है या शायद समुदायों का समुदाय है, परन्तु, वह एक समाज अथवा एक परिवार नहीं है। किसी समूह की सदस्यता व्यक्ति की वैयक्तिकता को कम नहीं करती, यह उसे विस्तृत करती है - लोगों को अकेले व्यक्तियों के रूप में उनकी ऐसी सीमाओं से स्वतंत्र करती है, उन्हें उनके अकेलेपन से मुक्त करती है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करती है। समाज के ऐसे दृष्टिकोण को व्यक्ति द्वारा स्वयं चयन की गयी सदस्यता की आवश्यकता होती है, थोपी गयी सदस्यता की नहीं।

17.3.4 राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरण की समस्या

स्वतंत्रतावादियों का यह दावा है कि स्वतंत्र बाज़ार ही केवल एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जो वैयक्तिक स्वतंत्रता का सम्मान करती है। उनके लिए स्वतंत्र बाज़ार गतिविधि की स्वतंत्रता का एक उदाहरण है। ऐच्छिक दोतरफा आदान-प्रदान ही स्वतंत्र बाज़ार का सार है: जब दो पक्ष किन्हीं वस्तुओं का ऐच्छिक रूप से आदान-प्रदान करते हैं, अथवा अपनी इच्छा अनुसार कोई समझौता करते हैं और यदि ऐसी प्रक्रिया दूसरों के अधिकारों की अवहेलना में ग्रस्त नहीं होती, वहाँ तक किसी को दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं होता। स्वतंत्रतावादियों के अनुसार, स्वतंत्र बाज़ार के समाज में व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐच्छिक समझौतों तथा आदान-प्रदान के समूह कहा जा सकता है - इसके अतिरिक्त न कम, न अधिक। स्वतंत्र बाज़ार के दायरे में हुआ कोई भी वितरण, जहाँ तक ऐसा वितरण किसी अन्य के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, न्यायसंगत है क्योंकि ऐसी अवस्था में आदान-प्रदान ऐच्छिक रूप से किए गए हैं। उदाहरणतः हेयक ने कहा है कि समाज में आचरण के नियम सदैव विकसित होते रहते हैं, वह तब तक बने रहते हैं जब तक समाज में वह उपयोगी होते हैं। वह कहते हैं कि बाज़ार समय के थपेड़ों को सहता हुआ बनता रहता है; सभी सफल समाज स्वतंत्र बाज़ार पर ही टिके रहे हैं; 'बाज़ार' अन्य सभी आर्थिक व्यवस्थाओं की अपेक्षा सर्वोच्च है, क्योंकि यह लाभ तथा संसाधनों के बीच कुशलतापूर्वक तरीकों से सन्तुलन बनाए रखता है। बाज़ार यदि ऐसा कर पाया है, तो इसलिए नहीं की

उसके समक्ष कोई पूर्व सुनिश्चित उद्देश्य थे, या वह लोगों के किन्हीं उद्देश्यों की मान्यताओं पर आधारित था; बाज़ार तो स्वयं अपनी आन्तरिक कार्यप्रणाली के कारण संतुलन बना पाया है। स्वतंत्रतावादी कहते हैं कि बाज़ार व्यवस्था तो स्वतंत्रता को स्वयं सहज बना देती है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवस्था का अपना क्षेत्र निश्चित होता है और कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता।

स्वतंत्रतावादियों की धारणा है कि बाज़ार इस तथ्य पर आधारित होता है कि लोग उतना अकेले रहकर प्राप्त नहीं कर पाते जितना, वह दूसरों के साथ सहयोग करके हासिल कर पाते हैं। यदि हम ऐसे जीव होते जिनके लिए सहयोग की अपेक्षा अकेले कार्य करना अधिक लाभकारी होता, तब हम मात्र अकेले अथवा छोटे छोटे कण तो होते ही, साथ ही, जैसे कि ल्युडबिग वान माइसिस ने कहा है कि 'हम एक दूसरे के शत्रु भी होते और अपने अपने स्वार्थों व लालसा के कारण अपने पड़ोसियों के साथ अनमनीय तनावों से घिरे हुए दिखाई देते'। श्रम विभाजन तथा सहयोग के गुणों के चलते ही सहानुभूति व मित्रता की भावनाएँ बढ़ सकती हैं तथा 'बाज़ार व्यवस्था' में व्यवस्था भी पनप सकती है। जो लोग यह कहते हैं कि 'व्यक्ति 'प्रतिस्पर्धा' के फलस्वरूप ही पनपते हैं, वह नहीं जानते कि बाज़ार स्वयं एक "सहयोग" है'।

बहुत लोग यह स्वीकार करते हैं कि 'बाज़ार' ज़रूरी होते हैं, परन्तु फिर भी वह महसूस करते हैं कि बाज़ार व्यवस्था में अनैतिकता होती है; उनसे असमानता पनपती है तथा बाज़ार में स्वार्थ का पो-गण होता है। कई बार 'बाज़ार' को 'पाश्विक' अथवा 'कुत्ता कुत्ते को खा जाता है' जैसे तत्वों से जोड़ा जाता है। परन्तु स्वतंत्रतावादियों का विश्वास है कि बाज़ार आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं; अधिकतर सहमति के गुणों से प्रेरित होते हैं: वह सरकार के अवपीड़न की अपेक्षा सदाचार तथा समानता की बढ़ोतरी करते हैं। ऐसा इन कारणों द्वारा होता है: (i) सूचना व समन्वय; (ii) कीमतें, (iii) उत्पादन में कुशलता, (iv) प्रौद्योगिकीकृत परिवर्तन, (v) प्रतिस्पर्धा। इस सदर्भ में स्वतंत्रतावादी निम्नलिखित तर्क देते हैं:

- 1) बाज़ार सहमति पर आधारित होते हैं; कोई भी व्यापारी बिना माँगे बिल नहीं भेजता; कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए विवश नहीं करता; व्यापारी यह खोजने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ताओं की क्या क्या ज़रूरत है; जो कुछ भी पैदा किया जाता है अथवा जिसका उत्पादन होता है, वह उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है, क्योंकि उत्पादनों का अधिक लाभ तभी हो पाता है, जब वह बाज़ार में उन वस्तुओं को बेचते हैं जिनकी उपभोक्ताओं को ज़रूरत होती है। उत्पादकों को उपभोक्ताओं की ज़रूरत से जुड़ी **सूचनाएँ** कहाँ से मिलती हैं। यह सूचनाएँ किसी बड़ी पुस्तक में लिखी हुई नहीं होतीं। बाज़ार अर्थव्यवस्था में, यह सूचनाएँ बाज़ार में होने/आने वाली माँगों द्वारा एकत्रित व उनका **समन्वय** किया जाता है।
- 2) लोगों की ज़रूरतों की सभी सूचनाएँ **कीमतों** से मालूम होती हैं। कीमतों का मतलब यह नहीं होता कि एक अमुक वस्तु पर कितना खर्च हुआ है और उसकी कितनी कीमत होनी चाहिए। कीमत व्यवस्था तो इन सभी सूचनाओं को सूचीबद्ध करती है (i) कि एक व्यक्ति की ज़रूरत क्या है; (ii) कि वह किसी वस्तु की क्या कीमत समझता/लगाता है; (iii) कि उस वस्तु को कहाँ पैदा किया जा सकता है। कीमतें ऐसी सूचनाओं को उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को उपलब्ध कराती हैं। प्रत्येक वस्तु की निर्धारित कीमत में यह सूचना निहित होती है कि उपभोक्ता की माँग क्या है; उत्पादन करने पर उस वस्तु, पर कितना खर्च आया है; मज़दूर को कितनी मज़दूरी दी

गयी है; वस्तु के बनाने तथा उसके बेचने के दौरान और कितना खर्च हुआ है; निर्मित वस्तु के लिए कच्चे माल पर क्या खर्च किया गया है। इन सूचनाओं के फलस्वरूप उत्पादकों को अपने उत्पाद उत्पादित करने में सहायता मिलती है। लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, तो उत्पादन भी अधिक होता है। कीमत-प्रणाली लाखों उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा संसाधन-स्वामियों (जो कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं) को अपने अपने प्रयासों को समन्वय करने में सहायता देते हैं। एक-दूसरे से मिले बिना संसाधन स्वामी अपने संसाधनों/कच्चे माल को, (किस भाव बेचना है) बेचने में सफल हो जाता है; उत्पादक जानता है कि उन्होंने कितना, कब तथा किस कीमत पर माल बनाना व बेचना है; उपभोक्ता जान लेता है कि उन्होंने क्या और किस कीमत पर कोई वस्तु खरीदनी है। दूसरी ओर, यदि ऐसा कार्य सरकार द्वारा हो, तो सरकार बहुमत का ध्यान रखते हुए वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर लेती है। परन्तु बाज़ार व्यवस्था में बेचने वाले व खरीदने वाले कीमतों को निर्धारित करते हैं।

- (3) उत्पादकों के बीच **प्रतिस्पर्धा**, वस्तु की कीमतें तथा उन वस्तुओं की **कुशलता** सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। उपभोक्ता वह वस्तु खरीदता है, जो उसे कम कीमत पर मिलती है तथा अच्छी गुणवत्ता/कुशलता में मिलती है।
- (4) बाज़ार में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा बाज़ार में बने रहने हेतु उत्पादक, अपने प्रतिस्पर्धी उत्पादक की निरन्तर प्रतिस्पर्धा में रहता है। बाज़ार में बने रहने हेतु उत्पादक अपनी वस्तुओं की कीमतों को तब कम करने की सोचता है, जब उसे अपने प्रतिस्पर्धी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहना होता है। कीमतों में कमी वह **प्रौद्योगिकी परिवर्तनों** के फलस्वरूप भी कर सकता है। बाज़ार व्यवस्था अपने आप प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा विकास की ओर बढ़ती रहती है।
- (5) बाज़ार व्यवस्था अति प्रतिस्पर्धात्मक होती है। प्रतिस्पर्धा द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि वस्तुओं को कैसे कम खर्च पर बनाया जा सकता है तथा किन से कम माल पर कच्चा माल लिया जा सकता है तथा श्रम सेवाओं पर कितना कम खर्च हो सकता है। इन आर्थिक गतिविधियों में थोड़ा भी हस्तक्षेप स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के कारण बाज़ार व्यवस्था से मिलने वाले लाभ के लिए हानिकारक हो सकता है। साधारण व्यक्ति को तो भौतिक कल्याण तथा आर्थिक लाभ अधिक प्रिय होते हैं। यदि लोगों को किस सीमा तक इन लाभों से वंचित किया जाता है, तो उस सीमा तक बाज़ार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी तथा वस्तुओं व सेवाओं का उस सीमा तक लाभ उठाना कठिन हो जाएगा। स्वतंत्रतावादियों के लिए तो मूल प्रश्न यह है कि समाज में सभी संसाधनों, मानव संसाधनों सहित, को एकत्रित करके कितना अधिक उत्पादन तथा कितने अधिक लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है।

स्पर्धा के माध्यम से नए ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है तथा उनमें समन्वय पैदा किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा में सभी एक बराबर लाभ नहीं उठा पाते, तथा कुछेक को शायद प्रतिस्पर्धा के कारण बाज़ार भी छोड़ना पड़ सकता है। स्वतंत्रतावादियों के लिए ऐसा होना बाज़ार में सृजनात्मक भनक है। भले ही उपभोक्ताओं का निर्णय कुछेक सख्त हो तथा कुछेक को शायद अपनी नौकरी व निवेश भी छोड़ना पड़े, परन्तु 'बाज़ार' प्रणाली तो समानता के नियम पर काम करती है। एक स्वतंत्र बाज़ार में किसी भी कम्पनी को सरकार की ओर से कोई विशेष-ाधिकार प्राप्त नहीं होते और इस कारण प्रत्येक को बाज़ार में ठहरने व बने रहने के लिए उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना ज़रूरी है। यह

आरोप कि बाज़ार व्यवस्था में स्व-स्वार्थ सर्वोसर्व होता है, वास्तविक स्थिति यह है कि बाज़ार प्रणाली तो दूसरों के स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करती है। बाज़ार तो ईमानदार को पुरुस्करित करता है क्योंकि लोग उससे व्यापार करना अधिक अच्छा समझते हैं जो ईमानदार होते हैं। बाज़ार तो सभ्यता को मान-सम्मान देता है, क्योंकि लोग शि-ट साझेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से सम्बन्ध बनाना अधिक श्रेयकर समझते हैं।

राज्य के सामाजिक-कल्याणकारी नीतियों के प्रयोग को सीमित रखने तथा बाज़ारी स्वतंत्रताओं की रक्षा हेतु, स्वतंत्रतावादी कर्षों से प्राप्ति राशि की पुनर्वितरण योजना का विरोध करते हैं। स्वतंत्रतावाद का मत है कि कर्षों की पुनर्वितरित योजना अपने आप में गलत है; यह लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। लोगों को अपनी वस्तुओं को स्वतंत्रतापूर्वक ढंग से बेचने का अधिकार है। जैसा कि नॉज़िक कहते हैं: 'लोगों के अधिकार होते हैं, यह ऐसी चीजें हैं जिन के लिए कोई व्यक्ति अथवा समूह कुछ भी नहीं कर सकता - ऐसा करने का अर्थ उनके अधिकारों का उल्लंघन करना है'। वह कहते हैं कि 'यह अधिकार इतने सशक्त व प्रभावकारी हैं कि किसी को भी, राज्य तथा अपने अधिकारियों को भी/उनकी अवहेलना का अधिकार नहीं है'। नॉज़िक ने इस संदर्भ में अपने "हकदारी सिद्धान्त" में बहुत कुछ कहा है।

हकदारी सिद्धान्त का मुख्य सार यह है कि 'यदि हम मान लें कि जो व्यक्ति के पास सम्पत्ति के रूप में हैं, उसके लिए वे हकदार हैं तो एक न्याययुक्त वितरण साधारणतः वह है जो लोगों द्वारा स्वतंत्र आदान-प्रदान के फलस्वरूप वितरित रूप में होगा'। कोई सा भी ऐसा वितरण जो स्वतंत्र हस्तांतरण द्वारा आदान-प्रदान होता है, वह ही न्याय युक्त है। सरकार द्वारा इन आदान-प्रदानों पर लगाया गया कर किसी पर भी कर न्यायसंगत नहीं है, भले ही ऐसे कर्षों की उन लोगों में ही क्यों न वितरित किया जाए जो प्राकृतिक रूप से विकलांग ही क्यों न हो। केवल एक मात्र कर लगाकर राजस्व एकत्रित करना, वहीं उचित है, जो स्वतंत्र आदान-प्रदान व्यवस्था की रक्षा हेतु बनायी गयी संस्थाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो - न्याय व्यवस्था तथा पुलिस व्यवस्था के लिए राजस्व एकत्रित करना उचित है, क्योंकि यह लोगों में स्वतंत्र आदान-प्रदान को कार्य रूप देते हैं। नॉज़िक हकदारी सिद्धान्त निम्नलिखित तीन नियमों पर आधारित है:

- 1) **हस्तांतरण का नियम:** जिसे न्याययुक्त ढंग से प्राप्त किया जाए, उसे स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित किया जा सके।
- 2) **उचित रूप से प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त करने का नियम:** लोग आरंभिक अवस्था में वस्तुओं को कैसे प्राप्त करते हैं, जिन्हे पहले नियम अनुसार हस्तांतरित किया जा सके।
- 3) **अन्याय के परिशोधन का नियम:** उन संप्राप्तियों को जिन्हें न्याययुक्त ढंग से प्राप्त न तो किया गया हो और न ही हस्तांतरित किया गया हो, उनके साथ क्या किया जाए।

उपर्युक्त नियमों को समझने/समझाने हेतु एक उदाहरण यह दिया जा सकता है: यदि मेरे पास एक प्लॉट है और मैं उसका न्यायपूर्ण ढंग से स्वामी हूँ, तो हस्तांतरण के नियम के अनुसार मैं इसका अपनी इच्छा अनुसार हस्तांतरण कर सकता हूँ; प्राप्ति का नियम बताता है कि मैंने इस प्लॉट को प्रारंभिक अवस्था में कैसे प्राप्त किया था। अन्याय के परिशोधन का नियम मुझे बताता है कि यदि पहले दोनों नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा। इन सभी को एकत्रित रूप में यदि देखा जाए यदि लोगों द्वारा प्राप्त वर्तमान वस्तुएँ न्याययुक्त ढंग से प्राप्त हुई हैं, तो न्यायसंगत वितरण का सूत्र

होगा: "प्रत्येक को वही जो वह चुनते हैं से प्रत्येक को वही जो उन्होंने चुना है। (From each as they choose to each as they are chosen.)

लोगों को हकदारी के दावे की स्वीकृति के लिए नॉज़िक दो तर्क देते हैं: (i) **सम्पत्ति का स्वतंत्र प्रयोग अधिक आकर्षक होता है;** (ii) **सम्पत्ति का अधिकार स्व-स्वामित्व को स्थापित करता है।** पहला तर्क यह स्पष्ट करता है कि यदि हमने किसी चीज़ को न्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त किया है, तो हमें उस पर पूरा अधिकार होना चाहिए: तभी हम उसे स्वतंत्र रूप से बेच भी सकते हैं, भले ही ऐसा करने से आय तथा अवसर के वितरण में भारी स्तर पर असमान ही क्यों हो। ऐसी स्थिति में जिनकी प्राकृतिक योग्यताएँ एक समान नहीं होंगी, उन्हें समान वितरण उपलब्ध नहीं होगा: कुछ को अधिक प्राप्ति होगी तथा कुछ को कम। नॉज़िक मानते हैं कि ऐसी स्थिति में सामाजिक सहयोग से मिलने वाले लाभ में असमानता होगी परन्तु समस्या यह है कि लोगों का अपनी आय पर अधिकार होना चाहिए। जैसा कि नॉज़िक कहते हैं, "किसी को भी कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिस की प्राप्ति उन गतिविधियों के प्रयोग से हो जो दूसरों के अधिकारों व हकदारी में आते हैं।" नॉज़िक का दूसरा तर्क यह है जिसका सम्बन्ध स्व-स्वामित्व के नियम से है। नॉज़िक का इस नियम से मतलब यह है कि लोगों को अपने-आप में साध्य समझा जाना चाहिए। उनके सिद्धान्त का सार यह है कि लोगों के अधिकार होते हैं तथा ऐसी वस्तुएँ होती हैं, जिन पर किसी अन्य व्यक्ति अथवा समूह का (उनके अधिकारों की अवहेलना किए बिना) का अधिकार नहीं होता। "समाज को इन अधिकारों का मान करना चाहिए, क्योंकि वह कानून के उस नियम के तथ्य को दर्शाते हैं जिसमें व्यक्ति को साधन न मानते हुए साध्य माना जाता है; लोगों को दूसरों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें बलि नहीं चढ़ाया जाता।" क्योंकि हम भिन्न दावों के लिए भिन्न व्यक्ति होते हैं, त्याग करने की भी अपनी सीमाएँ होती हैं, किसी को किसी अन्य के लिए कुरबान नहीं किया जाता। स्वतंत्रतावादी व्यक्तियों के साधन अथवा संसाधन नहीं समझते, बल्कि ऐसे मनु-य समझते हैं, जिनके प्रति-ठा सहित अपने अधिकार होते हैं। सारांश यह है कि हकदारी सिद्धान्त का यह मत है कि लोगों को स्व-स्वामी समझने का अर्थ है, उन्हें एक दूसरे के समान समझना और केवल अप्रतिबंधित पूँजीवाद ही स्व-स्वामित्व को मान्यता प्रदान करता है।

17.3.5 विधि का शासन तथा सीमित सरकार

स्वतंत्रतावाद व्यभिचार अथवा सुखवाद नहीं है। यह कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि लोग जो चाहें कर सकते हैं और कि कोई उन्हें कुछ कर नहीं सकता। इसके विपरीत, स्वतंत्रतावाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है, जहाँ कानून के दायरे में स्वतंत्रता विद्यमान होती है, जहाँ दूसरों के समान अधिकारों का मान-सम्मान करते हुए लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र होते हैं। विधि के शासन का अर्थ है: सामान्य एवं स्वैच्छिक विकसित कानूनी नियमों द्वारा शासित किया जाना, न कि मनमाने आदेशों द्वारा। ऐसे विधि के शासन के अंतर्गत कानूनों द्वारा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, ताकि लोग अपने सुख की प्राप्ति कर सकें, ऐसे कानूनों का उद्देश्य किन्हीं विशेष लक्ष्यों/ परिणामों की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए।

अधिकारों की रक्षा के लिए लोग सरकारें बनाते हैं। परन्तु सरकार तो एक खतरनाक संस्था है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्वतंत्रतावाद सामाजिक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। हेयक ने अपनी रचना, *द रोड टू सर्फ़डम*, में यह चेतावनी दी थी कि कल्याणकारी/समाजवादी नीतियों के अनुसरण के फलस्वरूप अंततः सर्वसत्तावादी सरकार की स्थापना होती है। वह कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का भवि-य यह माँग करता है कि समाजवादी विचारों का खण्डन किया जाना चाहिए तथा

क्लासिकी उदारवाद की पुनः स्थापना की जानी चाहिए। पहले के उदारवादियों की भांति, हेयक राज्य को शत्रु मानता है तथा निजी सम्पत्ति के अधिकार को व्यक्तियों के अधिकारों पर एक प्रहार समझता है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य के दायरे में, मिल्टन फ्रीडमन ने कहा कि प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति से अलग करता है और इस प्रकार राज्य को दूसरे के लिए प्रतितुलित करता है। एक और लेखक राल्फ डेहरण्डार्फ ने मत व्यक्त किया कि कल्याणकारी राज्य दफतरशाही का लौह-पिंजर पैदा करता है तथा उन्होंने कुछ सीमा तक सरकार व राज्य के विरुद्ध पारंपरिक उदारवादी संदेह ज़ाहिर किया। उन्होंने लिखा है, "ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, जिसे कि हम परोपकारी सरकार कहते हैं। सरकार तो एक अभागी आवश्यकता है। यह सदैव लोगों की स्वतंत्रताओं पर आक्रमण करती है। इसके अतिरिक्त, ज़रूरत कम प्रकार की सरकार की है।"

न्यूनतम राज्य से जुड़ी स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण की एक सशक्त परिभाषा नॉज़िक ने अपनी पुस्तक *अनारकी, स्टेट एण्ड यूटोपिया*, में दी है। नॉज़िक वैयक्तिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की चर्चा करते हैं। जॉन लॉक की परम्परा का अनुसरण करते हुए नॉज़िक कहते हैं कि समाज से स्वतंत्र लोगों के पास पहले तथा अहस्तांतरीय अधिकार थे। वह बताते हैं कि अधिकार व्यक्ति की सम्पत्ति होते हैं, और वह इतने सशक्त तथा दूरगामी होते हैं कि कोई भी, राज्य सहित, उनके विरुद्ध कुछ न कर सकने के लिए शक्तिहीन होता है। वास्तव में, यह अधिकार राज्य के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। अधिकारों के संदर्भ में राज्य क्या कर सकता है? उसका स्वरूप क्या है? उसके वैधपूर्ण कार्य क्या हैं? उसका औचित्य क्या है? नॉज़िक के अनुसार, राज्य न्यूनतम होना चाहिए तथा उसकी शक्तियाँ बल, चोरी, कपट आदि के उन्मूलन तथा समझौतों को कार्यरूप देने आदि तक सीमित होनी चाहिए। इससे अधिक कार्य यदि सरकार को दिए जाते हैं, तो वह लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तथा उस सीमा तक राज्य का कोई औचित्य नहीं होगा। नॉज़िक कहता है कि न्यूनतम राज्य प्रेरणापरक तथा उपर्युक्त दोनों होगा। ज़रूरी यह है कि राज्य को कुछ नागरिकों की सहायता के लिए कुछ पर उत्पीड़न यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और लोगों को अपने हित तथा अपनी सुरक्षा हेतु उनकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगानी चाहिए।

क्योंकि नाज़िक लोगों के अधिकारों में आस्था रखता है, इसलिए वह अराजकतावादियों के दावे को गंभीरता से लेते हैं जबकि वह राज्य को लोगों के अधिकारों को, बल के प्रयोग द्वारा, हनन किए जाने और इस कारण राज्य को अनैतिक घोषित करते हैं। इस दावे के प्रतिकूल, नॉज़िक का तर्क यह है कि भले लोग न चाहे, राज्य अराजकता से पनपना है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपने हित में एक प्रभुत्वकारी सुरक्षात्मक संस्था बनाए रखने को श्रेयकर समझेंगे जिसे बल प्रयोग का वास्तविक एकाधिकार होगा। राज्य रूपी ऐसी संस्था को यदि उचित रूप से उसे बनाया जाए, तो वह किसी के अधिकारों की अवहेलना नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में, ऐसे राज्य के पास सुरक्षा, न्याय तथा प्रतिरक्षा के वैधपूर्ण शक्तियाँ ही होंगी और ऐसा राज्य इन शक्तियों के प्रयोग के परे जाएगा ही नहीं। न्यूनतम राज्य के औचित्य को सही मानते हुए नॉज़िक स्पष्ट-तः इस तथ्य पर बल देते हैं कि स्वतंत्रता को समानता पर पूर्ण रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वह क्रमिक कर लगाए जाने तथा सकारात्मक विभेद की नीतियों का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के मार्ग में सरकार की जनस्वास्थ्य रक्षण, शिक्षा तथा न्यूनतम आजीविका स्तर की सरकारी नीतियाँ बाधाएँ नहीं बननी चाहिए। वह तर्क देते हैं कि जिनके पास धन है, वह स्वेच्छा से पुनर्वितरण से जुड़े कुछ कदम उठा सकते हैं। वह राज्य द्वारा सम्पत्ति के पुनर्वितरण का विरोध इस आधार पर करते हैं कि ऐसा होने से जिनके पास

सम्पत्ति होती है, उनकी स्वतंत्रता भंग होती है। नॉज़िक के लिए, राज्य एक रात्रि पहरेदार से अधिक कुछ नहीं है, जो नागरिकों के अहस्तांतरित अधिकारों की रक्षा करता है। वह इस तथ्य पर भी बल देता है कि कल्याणकारिता की संकल्पना जो समाज को संसाधनों के निर्धारण का दायित्व सौंपती है, वह अपने आपमें गलत तथा अवैध संकल्पना है क्योंकि समाज जैसी कोई संस्था नहीं होती, सिवाए इसके कि यह लोगों का एक समूह मात्र है। उनके अनुसार, "अपने वैयक्तिक जीवन से जुड़े वैयक्तिक लोग होते हैं तथा समाज मात्र ऐसे व्यक्तियों के योगफल के अलावा कुछ नहीं। राज्य हस्तक्षेप का मतलब किसी ने 'स्वत्व' तथा किसी के 'संसाधनों' को हड़पना है, किसी के श्रम को हथियाना, उस समय को हथियाना है, जिसका वह श्रम है और उस समय को किन्हीं और गतिविधियों को कराने के लिए जुटाना है। यदि लोग आपको कोई काम करने के लिए विवश करते हैं अथवा कुछ समय के लिए बेगार कराते हैं, वह ही यह निर्णय करते हैं कि आपने क्या करना है तथा किस उद्देश्य के लिए काम करना है। आपके लिए उनका यह निर्णय करना, उनको आपका आंशिक स्वामी बना देता है; ऐसा करने का अर्थ है कि आप उनकी सम्पत्ति बन गए हैं।" इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य लोगों की स्वतंत्रता के लिए खतरा होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपंग तथा अपनी योग्यता का स्वयं स्वामी होता है।

किस सीमा तक अहस्तक्षेपी, न्यूनतम तथा बाज़ार प्रभुत्व प्रकार के स्वतंत्रतावादी राज्य औचित्य है? इस संदर्भ में नॉज़िक के विचार व्यक्ति के कुछेक अहस्तांतरित अधिकारों पर आधारित हैं, जो समाज से स्वतंत्र व्यक्ति के पास होते हैं। आज व्यक्ति को अनेक ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, जो कभी प्राचीन युगीन व मध्यकालीन युग में लोगों को प्राप्त नहीं थे। यह याद रहना चाहिए कि अधिकार अपने स्वरूप में ऐतिहासिक व सामाजिक होते हैं। वास्तव में, नॉज़िक जिन अधिकारों का समर्थन करते हैं, वह ऐतिहासिक रूप से बाज़ार व्यवस्था तथा पूंजीवादी सम्बन्धों के संदर्भ के अधिकार थे; वह न तो प्राकृतिक अधिकार थे और न ही राज्य से पहले की अवस्था के अधिकार थे। इस संदर्भ में यह युक्ति दी जा सकती है कि यदि 'बाज़ार' ने संसाधनों की बाँट करनी है, तो पूंजीवादी समाज में ऐसी बाँट समानांतर नहीं हो सकती; 'बाज़ार' स्वयं अपने उत्पादन तथा विनिमय की व्यवस्था में कुछ को कुछ अन्यों की अपेक्षा विशेष-आधार देता है। अतः यह विचार कि स्वतंत्र तथा संप्रभुता प्राप्त व्यक्ति अपने संसाधनों का चयन स्वयं कर लेगा, अपने आपमें एक मिथक है। नॉज़िक का न्यूनतम राज्य का विवरण कराधान के किसी सिद्धान्त के अभाव में विफल प्रयास है। यही कारण है कि अन्य स्वतंत्रतावादी विद्वान एकसूत्रीय लागू सामान्य नियमों के अनुसार कराधान पर बल देते हैं। उदाहरणतः हेयक तथा फ्रीडमैन का कहना है कि एक आनुपातिक प्रकार का करारोपण स्वतंत्रतावादी विचार-योजना के अनुरूप होगा। उनके अनुसार, आनुपातिक करारोपण धनी परन्तु अलौकिक अल्पवर्ग पर कर-राशि पुनर्वितरण को थोपने से रोकेगा और इस प्रक्रिया में धन-नीति में मनमानेपन के क्षेत्र को भी समाप्त करेगा। वह कहते हैं कि कराधान नीति सामान्य नियमों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि सरकार आर्थिक स्वतंत्रता का दमन न कर पाए।

सारांश यह है कि स्वतंत्रतावादियों द्वारा प्रतिपादित सीमित सरकार की संकल्पना राज्य को स्थायी रूप से एक आवश्यक बुराई मानती है। ऐसा करके स्वतंत्रतावाद एडम स्मिथ जैसे विचारकों की अंतर्दृष्टि का लोहा मानता है। हेयक स्वयं स्वीकार करते हैं कि सामाजिक जीवन स्वचालित व्यवस्था है, परन्तु ऐसी स्वचालित व्यवस्था के लिए ऐसी वैधानिक संस्थाएँ तभी उपयोगी हो सकती हैं, जब सबको स्वतंत्रताओं की सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हो। स्वतंत्रतावादियों की राज्य की संकल्पना का उस प्रकार की सरकार की संकल्पना का विरोध करना है, जो सामान्य कल्याण की रक्षा करती है तथा उसमें वृद्धि करती है; जो सामान्य हित में मनमानी शक्तियों का प्रयोग करती है; स्वयं में एक निर्बल

सरकार होती है; कमज़ोर इस दृष्टि से वह तनावग्रस्त हित समूहों का शिकार बनी रहती है और उस प्रक्रिया में मूल स्वतंत्रताओं की रक्षा करने में विफल रहती है।

17.4 vkykpkukRed मूल्यांकन

अनेक आधारों पर स्वतंत्रतावाद की आलोचना की जाती है: उसके अधिकारों के सिद्धान्त, स्वतंत्रता की प्रकृति, राज्य की भूमिका, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, संसाधनों के पुनर्वितरण की समस्या आदि आधार पर स्वतंत्रतावाद पर प्रहार किया जाता है।

- कुछ स्वतंत्रतावादियों का तर्क है कि हम कुछेक अधिकारों के साथ जन्म लेते हैं, अर्थात् अधिकारों सहित इस दुनिया में आते हैं: जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के अधिकारों सहित। उनका कहना है कि इन अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि केवल इन अधिकारों का ही क्यों, अन्य अधिकारों का क्यों नहीं? स्वतंत्रतावादियों का उत्तर यह है कि केवल ऐसे अधिकार ही लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने में सहायक होते हैं; यह अधिकार ही उन्हें अपने आपमें साध्य, न कि दूसरों के लिए साधन, रूप में दर्शाते हैं तथा यह अधिकार ही व्यक्तियों को उनके अलग अस्तित्व की पहचान प्रदान करते हैं। परन्तु यह तर्क इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते कि यह अधिकार प्राकृतिक क्यों हैं? हैमर्टन के अनुसार, ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि हम यह कहें कि अधिकार प्राकृतिक हैं: समाज के कानून से स्वतंत्र किसी पूर्व-अवस्था के अधिकार।
- इसमें संदेह नहीं है कि लोगों को साध्य बताना अच्छा है। इस तथ्य से भी सहमति हो सकती है कि यदि लोगों को कुछ रखने का अधिकार नहीं है, तो उन से आगे की योजना बनाने की आशा नहीं की जा सकती। तथापि यह तर्क दिया जा सकता है कि लोगों को जीवित रहने के लिए उनके पास आवश्यक संसाधनों का होना दूसरों के दिए जाने वाले सम्मान के अनुकूल है। यदि किसी के पास छत नहीं है, काम नहीं है, धन नहीं है, उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने भवि-य के लिए कोई प्रभावपूर्ण योजना बना सकता है, क्योंकि वह दूसरों के निर्णयों पर निर्भर होता है कि उसके लिए स्वयं जीवित रह पाना भी कठिन है। अतः किसी को संसाधनों की ऐसी उपलब्धि हो कि वह अपनी कठिनाइयों से ऊपर उठ सकता है, दो आधारों पर सहायक है: किसी को अपने आप का साध्य समझने के लिए तथा उसे अपने भवि-य की योजना बनाने हेतु। किसी के लिए ऐसी स्थिति तभी हो सकती है, जब सरकार अमीर लोगों पर कर लगाए, जो स्वतंत्रतावादियों को स्वीकार नहीं है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती और गरीब को भूखा छोड़ देती है, तो आप फिर ऐसे नियम को तोड़ रहे हैं जो किसी को जीवन देने पर ज़ोर देता है; सरल बात यह है कि एक स्वतंत्रतावादी समाज में जिनके पास सम्पत्ति नहीं है, वह परतंत्र हैं। ऐसे लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि कोई अन्य लोग उनकी सहायता नहीं करते अथवा अपनी सम्पत्ति का प्रयोग करने की आज्ञा नहीं देते। स्वतंत्रतावादी स्वतंत्रता की बात करते हैं और स्वतंत्रता के लिए अधिकारों के संरक्षण की चर्चा करते हैं। अतः स्वतंत्रतावादियों का यह दृष्टिकोण कि क्या वैधपूर्ण अधिकार हैं, स्वीकारीय नहीं है।
- आलोचक स्वतंत्रतावादियों की स्वतंत्रता की इस परिभा-ना कि यह उत्पीड़न का अभाव है, स्वीकार नहीं करते। यदि हम स्वतंत्रता की इस परिभा-ना को स्वीकार करते हैं, तो एक व्यक्ति की

स्वतंत्रता उस सीमा तक स्वतंत्रता होगी जब तक वह बिना किसी दूसरे की उत्पीड़नता के तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर सकने की (अथवा न कर सकने की) क्षमता रखता होगा। एक स्वतंत्रतावादी समाज में कोई यदि चाहे भी, किसी की सम्पत्ति के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। अतः आपकी प्रत्याभूत स्वतंत्रता आपके पास सम्पत्ति मात्रा द्वारा निर्धारित होगी। परिणामस्वरूप, जिसके पास सम्पत्ति नहीं होगी, उसके पास आश्वस्त स्वतंत्रता भी नहीं होगी तथा जिसके पास जितनी अधिक सम्पत्ति होगी, उसके पास आश्वस्त सम्पत्ति भी अधिक होगी। दूसरे शब्दों में, सम्पत्ति का वितरण स्वतंत्रता का वितरण होगा - जैसा कि स्वतंत्रतावादी स्वयं इसे परिभाषित करते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा तथा स्वतंत्र बाज़ार में विश्वास दोनों के दायरे में, स्वतंत्रतावादी यह कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि कुछ लोगों को दूसरों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता हो, भले ही इससे इस क्रम में भले ही कुछ की स्वतंत्रता कम क्यों न हो। दूसरे शब्दों में, यद्यपि स्वतंत्रतावादी प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान आश्वस्त स्वतंत्रता की माँग करते हैं, परन्तु 'बाज़ार' प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता की सीमा सबके लिए समान नहीं प्रदान करता। और फिर, किसी की सम्पत्ति होने का मतलब निश्चित रूप से उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। यह देखा गया है कि सभी प्रकार के समाजों में स्वतंत्रता को किसी न किसी रूप में सीमित किया जाता है। स्वयं स्वतंत्रतावादी भी स्वतंत्रता पर किन्हीं सीमाओं को स्वीकार करते हैं, जैसे लोग किसी के सम्पत्ति के अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकते। सत्य तो यह है कि यदि किसी भूखे को भूख की पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए अमीर पर कर लगाया जाए, तो उस अमीर पर लगायी गयी सीमाएँ बहुत कम हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि स्वतंत्रतावादी स्वतंत्रता की परिभाषा कुछ इस प्रकार करें कि उसका सम्पत्ति के वितरण में विच्छेदन हो।

- स्वतंत्रतावादी स्वतंत्रता को बल दीक्षित अभाव में देखते हैं। स्वतंत्रता की यह परिभाषा भी कुछ अधिक सहायक नहीं है। सम्पत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए बल की पहल की जा सकती है तथा सम्पत्ति अधिकार बिना बल की पहल में उल्लंघित हो सकते हैं (जैसे प्रकाशानाधिकार अवहेलनाएँ)। वह स्वतंत्रतावादी जो स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, यह दावा नहीं कर सकते, भले वह ऐसा चाहते ही क्यों न हों, फिर वह बल के पहल करने के विरुद्ध हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने अधिकार के दायरे में, किसी अन्य के आपके विरुद्ध बल की पहल किए बिना, कुछ भी कर सकते हैं। तथापि ऐसी सोच पुनः उस तथ्य की ओर ले जाती है, जब सम्पत्ति के अधिकार आपकी प्रत्याभूत स्वतंत्रता को निश्चित करते हैं। स्वतंत्रता का निर्धारण इस बात से जुड़ जाता है कि एक व्यक्ति के वैधपूर्ण अधिकार कौन से हैं। यदि स्वतंत्रतावादियों का मत है कि सम्पत्ति का अधिकार निरंकुश है, तो स्वतंत्रता और सम्पत्ति एक हो जाते हैं और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। हैमर्टन इसे 'सम्पत्तिवाद' कहता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्पीड़नहीनता कोई निरंकुश अच्छाई नहीं होती, और कई तथ्य उस पर भारी पड़ते हैं। उदाहरणतः यदि सब कुछ एक समान है, तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए उत्पीड़न करना गलत नहीं है। यदि उत्पीड़न का विकल्प अनवीनता है, तो नवीनता लाने के लिए उत्पीड़न वैध होता है। स्वतंत्रतावादी कहते हैं कि वह राजनीतिक स्वतंत्रता में आस्था रखते हैं। स्वतंत्र बाज़ार के नियमों को कार्य रूप देने के लिए राज्य यंत्र आवश्यक होता है - आक्रमण की रोक के लिए सेना चाहिए, आन्तरिक विद्रोह को दबाने के लिए पुलिस चाहिए, एक न्यायिक व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्य में बाध्यकारी यंत्र चाहिए। अनेक स्वतंत्रतावादी तो उससे भी आगे जाते हैं; वह स्वतंत्रतावादी प्रणाली, तथा स्वतंत्रतावादी राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं। कुछ स्वतंत्रतावादियों ने तो विस्तृत तथा पूर्णतः

संविधान लिखे हैं। किसी भी अन्य राज्य की भांति, एक स्वतंत्रतावादी राज्य को भी अपना संविधान तो लागू करना होगा, अन्यथा वह संविधान एक प्रस्तावित रूप में ही रह कर रह जाएगा। यदि राज्य को मंगल ग्रह पर ही क्यों न स्थापित किया जाए; कभी तो कोई, विभिन्न विचारों सहित, वहाँ पहुँचेगा। स्वतंत्रतावादी संविधान किसी हाल में स्थापित स्वतंत्रतावादी कालोनी में प्रतिबद्ध स्वतंत्रतावादियों द्वारा आवासीय हो। परन्तु देर-सवेर उन स्वतंत्रतावादी स्थापित नियमों के विरोध में कोई प्रतिपक्ष खड़ा होगा। ऐसे राज्य जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बचाने हेतु विरोध का मुकाबल नहीं कर पाते, उनका या तो पतन हो जाता है या वह लुप्त हो जाते हैं। यदि स्वतंत्रतावादी राज्य बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें आंतरिक प्रतिद्वन्द्वियों के विरुद्ध राजनीतिक दमन का प्रयोग करना पड़ेगा।

- अराज्यत्ववाद (Anti-Statism) स्वतंत्रतावाद का एक केन्द्रीय तत्व है, परन्तु, यह स्वतंत्रतावादी सिद्धान्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य नीवों पर आधारित है। कई स्वतंत्रतावादी राज्य को अंतर्निहिततः गलत बताते हैं। भले ही वह ऐसा स्प-टतः कहते हैं, ऐसा कहना मात्र उनका विश्वास है और कुछ नहीं। अपनी प्रकृति स्वरूप राज्य जिस प्रकार के उत्पीड़न का प्रयोग करता है, स्वतंत्रतावादी उसका विरोध करते हैं। परन्तु, राज्य द्वारा ऐसा उत्पीड़न गलत भी नहीं है। दूसरी ओर, स्वतंत्र बाज़ार को बनाए रखने हेतु राज्य उत्पीड़न के प्रयोग को स्वतंत्रतावादी सहन भी करते हैं तथा स्वागत भी। राज्य तो बाज़ार की शक्तियों के प्रतिकूल और भी समाज में बड़े-बड़े परिवर्तन तथा नवीनताएँ लागू करने का साधन है। आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य का मौलिक कार्य नवीनता लाना है - रा-ट्रीय परम्परावाद के विरोध में नवीनता; लोगों की इच्छा के प्रतिरोध में नवीनता, जब आवश्यक हो जाए; बाज़ार शक्तियों या बाज़ार तर्क के विरोध में नवीनता। अपने सुरक्षात्मक कार्यों के अतिरिक्त, राज्य को विवादों के अंतिम मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभानी पड़ती है, ताकि मनमानी प्रक्रियाओं का अंत किया जा सके। अनेक स्वतंत्रतावादी आज राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निजीकरण चाहते हैं। राज्य में निजीकरण लाने के लिए भी स्वतंत्रतावादियों को राज्य शक्ति की ज़रूरत तो पड़ेगी, एक कार्यात्मक स्वतंत्रतावादी राज्य को भी राज्य तंत्र तो चाहिए ही।
- स्वतंत्रतावादियों के आलोचकों का मत है कि धन का पुनर्वितरण गलत नहीं है। स्वतंत्रतावादियों का कहना है यह तो अमीर से प्राप्त वैधपूर्ण ढंग की सम्पत्ति चुराना है और उसे गरीब को देना है। उदाहरणतः नॉज़िक के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अपने ऊपर का अधिकार है - स्व-स्वामित्व का अधिकार। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति क्या है तथा जो व्यक्ति के पास है, दोनों एक ही हैं। मतलब यह हुआ, यदि मैं मेरा हूँ, तो योग्यता भी मेरी है और योग्यता से मैं, जो मुझे प्राप्त होता है, वह भी मेरा है। अतः योग्य व्यक्ति से कम लाभान्वित को पुनर्वितरण की माँग स्व-स्वामित्व की अवहेलना है। रॉल्स जैसे समतावादी का विश्वास है कि भले एक व्यक्ति अपनी योग्यता का कानूनन स्वामी हो, फिर भी योग्यता तो पाश्विक भाग्य का मामला होता है। अतः योग्यता का अधिकार योग्यता के प्रयोग से मिलने वाला असमान पुरस्कार प्राप्ति नहीं बन जाता। यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से अलाभान्वितों का लाभान्वितों पर कोई न कोई दावा होता है: सक्षमों को अपनी योग्यता का तभी लाभ होता है, यदि यह योग्यता अलाभान्वितों को भी उपलब्ध हो। अन्यों का विश्वास है कि धन का पुनर्वितरण स्वतः एक अच्छाई है; यह राज्य का एक नैतिक दायित्व है। अधिक मात्रा का धन, तो पुनर्वितरित होने के लिए होता है। प्रश्न केवल इतना है कि आधिक्य है क्या? इसमें संदेह नहीं है कि आधिक्य हेतु उत्पीड़नता होती है। परन्तु ऐसा गलत नहीं है, कदापि गलत नहीं।

स्वतंत्रतावादियों का यह मत कि उदारवादी कल्याणकारी कार्यक्रम सम्पत्ति के अधिकारों को सीमित कर लोगों के आत्म-निर्णय को सीमित करते हैं, समतावादियों को स्वीकारीय नहीं है। पुनर्वितरण कार्यक्रम संभ्रात व्यक्तियों के आत्मनिर्णय को कुछ सीमा तक सीमित अवश्य करते हैं, परन्तु वह उनको अपने-अपने जीवन पर नियंत्रण करने का अधिकार भी देते हैं जो उनके पास पहले नहीं था। उदारवादी पुनर्वितरण आत्म-निर्णय को किसी अन्य लक्ष्य के लिए नहीं त्यागता। यह तो साधनों के उचित वितरण के उद्देश्य को प्राप्त करता है, जो आत्म-निर्णय के लिए आवश्यक होता है। स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण, वितरण में अनुचित असमानताओं को जन्म देता है, जो उनको क्षति पहुँचाते हैं जिन्हें अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए उसकी ज़रूरत होती है।

स्वतंत्रतावादी सोच तथा स्वतंत्रतावादी वास्तविकता के अन्तर को एक आलोचक ने इस प्रकार बताया है: (i) स्वतंत्रतावादी अवपीड़नहीनता तथा बल की पहल न करने में विश्वास रखते हैं जबकि वास्तविकता में स्वतंत्रतावादी आर्थिक अन्याय को वैध मानते हैं और इस प्रकार के अन्याय को बनाए रखने में अवपीड़न बल-प्रयोग को अवपीड़न तथा बल की पहल मानते ही नहीं हैं; (ii) वह व्यक्ति की नैतिक स्वायत्तता पर आश्रित रहते हैं, जबकि वास्तविकता में स्वतंत्रतावादी व्यक्ति से बाज़ार शक्तियों के परिणामों को स्वीकार किए जाने की माँग करते हैं; (iii) स्वतंत्रतावादी राजनीतिक स्वतंत्रता में आस्था रखते हैं, परन्तु साथ में वे यह भी कहते हैं कि गैर-स्वतंत्रतावादियों पर स्वतंत्रतावादी नीतियों को लागू करने के लिए किसी न किसी प्रकार की स्वतंत्रतावादी सरकार ज़रूरी होगी; (iv) स्वतंत्रतावादी वर्तमान राज्यों को दमनकारी समझते हुए उनका खण्डन करते हैं, परन्तु वे ऐसे राज्यों से अपनी नीतियों को कार्य रूप दिलाने के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा भी करते हैं; (v) वह स्वतंत्रतावाद के गुणों की डींगें मारते हैं, परन्तु दूसरों के लिए क्या गुण/लाभ हैं, उस पर निर्णय स्वयं करने के अधिकार की माँग भी करते हैं।

उपर्युक्त कहा गया है कि स्वतंत्रतावाद राजनीतिक दर्शन में एंग्लो-अमेरिकी परम्परा का एक हिस्सा है। वास्तव में स्वतंत्रतावाद प्रचलित व्यवस्था, विशेष-तः अमेरिकी व्यवस्था, का वैधीकरण है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएँ वैधीकरण की विचारधाराओं का प्रयोग करती हैं, जो उन्हें राजनीतिक शक्ति के प्रयोग के लिए नैतिक औचित्य प्रदान करती हैं। स्वतंत्रतावाद कोई क्रान्तिकारी विचारधारा नहीं है, उस रूप में तो बिल्कुल भी नहीं, जो समाज के मौलिक मानकों को उखाड़ फेंकती हो। वास्तव में, अनेक अमेरिकी स्वतंत्रतावाद अमेरिकी मूल मानकों को बनाए रखने हेतु पारम्परिक रूढ़ि रखते हैं। स्वतंत्रतावाद विशेष-तः स्वतंत्र बाज़ार तथा उससे बनी सामाजिक असमानताओं का वैधीकरण करता है; यह अमीर का वैधीकरण है। स्वतंत्रतावादी रूढ़िवादी भी हैं - उनकी रुचि स्वतंत्र बाज़ार में नहीं है, अपितु इन सबके होने से उनके प्रभावों में हैं। शायद जो स्वतंत्रतावादी चाहते हैं, वह है : नवीनता को रोकना; सामाजिक परिवर्तनों की व्यवस्था को उलटना; कुछ सीमा में पुनः अतीत की ओर जाना।

17.5 सारांश

स्वतंत्रतावाद गत 20-30 वर्षों की अमेरिकी राजनीतिक विचारधारा है। यह वह राजनीतिक दर्शन है जिसने 1980 के दशक में थैचर/रीगन सरकारों को प्रभावित किया - नव दक्षिणवाद के सार को छूने वाली विचारधारा। इसके प्रवक्ताओं में एफ. ए. हेयक, मिलटन फ्रैडमेन, कार्ल पॉपर, तालमान, आई. बर्लिन, एम. राथबार्ड, राबर्ट नॉज़िक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसकी मुख्य संकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं:

व्यक्तिवाद : स्वतंत्रतावादी व्यक्ति को सामाजिक विश्लेषण की मूल इकाई मानते हैं; व्यक्ति ही प्राथमिकताएँ सुनिश्चित करते हैं; वह ही अपनी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं; स्वतंत्रतावादी व्यक्ति की प्रति-ठा पर बल देता है, जो उसके अधिकारों तथा दायित्वों को ज़रूरी बताता है।

वैयक्तिक अधिकार : क्योंकि व्यक्ति नैतिक पात्र होते हैं, इसलिए स्वतंत्रतावादी उनके सुरक्षित जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के अधिकारों पर बल देते हैं। स्वतंत्रतावादियों का मत है कि व्यक्ति के पास यह अधिकार उन्हें सरकार या समाज द्वारा प्राप्त नहीं होते; वह कहते हैं कि लोगों के पास यह अधिकार उनको व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकारों का व्यक्ति के पास होना ज़रूरी है; यह तो उनके लिए बोझ/दबाव है, जो उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं।

साहसिक/स्वाभाविक व्यवस्था: लोगों के जीवित रहने व पनपने के लिए समाज में व्यवस्था का होना ज़रूरी होता है। सामाजिक विश्लेषण में स्वतंत्रतावादियों की विशेषता यह है कि वह इस तथ्य पर जोर देते हैं कि समाज में व्यक्ति स्वाभाविक/सहज होता है - हज़ारों लोगों द्वारा पारस्परिक गतिविधियों के क्रम में अपने आप समन्वय पैदा होता है, जिसके अंतर्गत लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। समाज में अनेक व्यवस्थाएँ - भा-गा, कानून, धन, बाज़ार आदि - अपने आप विकसित हो जाते हैं, बिना किसी नियोजन व निर्देशन के। नागरिक समाज स्वाभाविक व्यवस्था का एक उदाहरण है। नागरिक समाज के अन्तर्गत विभिन्न समुदायों के अपने अपने विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, परन्तु, नागरिक समाज का कोई अपना लक्ष्य नहीं होता। नागरिक समाज कोई गठन नहीं है, यह तो ताना-बाना है, स्वचालित व्यवस्था।

स्वतंत्र बाज़ार : ज़िन्दा रहने तथा विकास करने के लिए लोग आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं। सम्पत्ति के अधिकार के साथ सम्पत्ति के आदान-प्रदान का अधिकार भी ज़रूरी बन जाता है, जिसका प्रयोग लोग परस्पर अनुबंधों में करते हैं। स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र बाज़ार अर्थव्यवस्था का काम करता है। इस कारण स्वतंत्र बाज़ार धन पैदा करने तथा जमा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। स्वतंत्रतावादियों का विश्वास है कि यदि लोगों की आर्थिक गतिविधियों में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, तो लोग अधिक स्वतंत्र तथा अधिक सम्पन्न होंगे।

न्यूनतम राज्य: अधिकारों की रक्षा के लिए लोग सरकारों का गठन करते हैं। परन्तु स्वतंत्रतावादी सरकार को खतरनाक संस्था समझते हैं। स्वतंत्रतावादी केन्द्रकृत शक्ति का विरोध करते हैं। वह सरकार की शक्ति को सीमित तथा कम करना चाहते हैं। सरकार की शक्तियों को सीमित रखने के लिए स्वतंत्रतावादी लिखित संविधानों द्वारा लोगों से प्राप्त सरकार की शक्तियों को कम करते हैं। सीमित सरकार स्वतंत्रतावाद की मूल राजनीतिक निहितार्थ है। राज्य को बल, चोरी, धोखेबाज़ी के विरुद्ध तथा अनुबंधों को कार्य रूप देने के लिए सीमित अधिकार होने चाहिए। राज्य के पास इससे अधिक शक्तियाँ व्यक्ति के अधिकारों के हनन का कारण बनती हैं, तथा उस सीमा तक उन शक्तियों को उचित नहीं माना जा सकता।

हितों में स्वाभाविक सहस्वरता: स्वतंत्रतावादियों का विचार है कि एक न्याययुक्त समाज में शान्तिपूर्ण लोगों के हितों में सहस्वरता होती है। अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए लोग योजनाएँ बनाते हैं - काम प्राप्ति की योजना, व्यापार शुरू करने की योजना, घर खरीदने की योजना आदि। अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों में परस्पर हित टकराते हैं। फलस्वरूप, बाज़ार व्यवस्था हमें अपनी योजनाओं को क्रम देने में सहायता करती है। स्वतंत्रतावादियों का विश्वास है कि स्वतंत्र बाज़ार की व्यवस्था के संचालन में हम सब सम्पन्न बनते हैं - किसानों व व्यापारियों में तनाव नहीं होते; उत्पादकों तथा आयात करने वालों में परस्पर विरोध नहीं होता। वह कहते हैं कि जब राजनीतिक दबाव में आकर सरकार

कुछेक पुरुस्कृत करती है, तो हम अनेक लोगों व समूहों में तनाव बढ़ते देखते हैं, उनमें प्रतिद्वंद्वता देखते हैं तथा राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति में होड़ देखते हैं।

शान्ति: स्वतंत्रतावादी युगों पुराने युद्ध परिणामों के भयानक नि-क-र्णों के विरुद्ध जंग छेड़े जाने का प्रचार करते हैं। उनका कहना है कि युद्ध अपने साथ, बड़े पैमाने पर, मृत्यु व विनाश लाते हैं, परिवारों को न-ट कर देते हैं, आर्थिक जीवन में बिखराव लाते हैं तथा शासकीय वर्गों के हाथों को और अधिक गठित कर देते हैं। यही कारण है कि शासकीय वर्ग कभी भी किसी प्रकार की शान्ति बनाए रखने के समर्थक नहीं रहे हैं। स्वतंत्र लोगों ने विदेशी आक्रमणों से अपने समाजों को बचाने के भरसक प्रयास किए हैं। परन्तु इतिहास साक्षी है कि युद्ध सदैव शान्तिप्रिय उत्पादी लोगों के हर कोण से शत्रु रहा है।

सारांश यह है कि स्वतंत्रतावाद में आधुनिक चिन्तन का मानकीय ढाँचा देखा गया है। उसमें व्यक्तिवाद, निजी सम्पत्ति, पूँजीवाद, कानून के समक्ष समानता तथा न्यूनतम राज्य जैसे सिद्धान्त हैं। इसमें इन सिद्धान्तों को पूर्ण रूप से तथा तर्कीय रूप से अपने विचारकों तथा किसी भी आधुनिक सरकार की अपेक्षा अधिक लागू करने का प्रयास किया जाता है।

17.6 अभ्यास प्रश्न

1. अपने शब्दों में स्वतंत्रतावाद के अर्थ की व्याख्या कीजिए।
2. नागरिक समाज पर एक निबन्ध लिखिए।
3. स्वतंत्रता के संदर्भ में वैयक्तिक अधिकारों की विवेचना कीजिए।
4. पुनर्वितरण की समस्या की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।